

भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या है, और प्रत्येक साल बेरोजगार व्यक्ति में एक ली है शुद्ध में सरकार ने दूध और लुप्त कम ध्यान दिया, और उनका मानना था कि विकास के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी स्वतः ही लुप्त जाएगी। लेकिन अब इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने दूध कम करने के लिए निम्न लिखित उपाय किए हैं।

(i) जनसंख्या नियंत्रण: → भारत में प्रतिवर्ष 80 लाख आदिकों की वृद्धि हो रही है इसका कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है सरकार ने दूध रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाये हैं।

(ii) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम: → भारत में बेरोजगारी की समस्या ज्यादातर गाँवों में है, इससे कम करने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएँ की जाती किचे हैं जैसे - काम के बहल अनज भोजना, गवाह रोजगार गारणो भोजना आदि।

(iii) विभिन्न रोजगार : → विभिन्न वर्ग में बेरोजगारी

कम करने के लिए कुछ विभिन्न कार्यक्रम भी अपनाये गए हैं जैसे 'स्कूलों' की संख्या बढ़ाकर नवीन अध्यापकों की नियुक्त किया गया है।

(iv) निर्भोजन सेवाएँ →

रोजगार दिलाने के लिए बेरोजगारों के मार्गदर्शन के लिए रोजगार कार्यालयों की संख्या में सरकार द्वारा वृद्धि की जा रही है। 1950 के अंत तक रोजगार कार्यालयों की संख्या 143 थी लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 947 कर दी गई है।

(v) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास : →

सरकार इन उद्योगों की सहायता के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सरकारी औद्योगिक सलाहकारी केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। वसई बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलती है।

(vi) बेरोजगारी भत्ता : →

विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं।

(vii) कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास : →

सरकार ने कृषि पर आधारित उद्योगों जैसे चीनी मिल, सूती वस्त्र मिल आदि नए उद्योग स्थापित किये जाने की बात की जा रही है और जो पहले से बन्द हैं उन्हें खोले जाने की भी बात की जा रही है।

उपरोक्त बातों से भले

स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा किये गए प्रयास सहायक हैं परंतु संतोषजनक नहीं हैं। इसके लिए सरकार को कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा जो अनिश्चित हैं।

(i) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन → वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसकी रोजगार-उन्मुख बनाया जाना चाहिए जिसके लिए व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार किया जा सकता है।

(ii) प्राकृतिक साधनों का संरक्षण → सरकार को प्राकृतिक साधनों का पता करके वहां पर संभावित नये-नये उद्योगों स्थापित करना चाहिए।

(iii) पूरी क्षमता का उपयोग → भारत में बहुत से उद्योग अपनी क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं अतः इस प्रकार के उद्योगों को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जिससे कि वृहत उद्योगों में रोजगार अवसरों की वृद्धि की जा सके।

(iv) गांवों में बिजलीघरों की स्थापना → गांव की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को बिजलीघरों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग चले पनप सके इसके अलावा —

(i) औद्योगिक सेवाओं की मंजूरत करना

(ii) जनशक्ति नियोजन आदि।

निष्कर्षतः उपर्युक्त ~~विचारों~~ ^{सुझाव} को ध्यान में रखकर अगले सरकार कार्य करेगी ताकि बेरोजगारी में काफी कमी आ सकती है।